मुख्यमंत्री ने खट्टर से ग्रीन एनर्जी व जयपुर मेट्रो पर चर्चा की

उन्होंने राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा निकासी परियोजना को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर-थर्ड में शामिल करने का आग्रह किया

■ मुख्यमंत्री भजनलाल ने जयपुर मेट्रो रेल फेज-2 के संयुक्त उपक्रम के तहत निर्माण की विस्तृत कार्य योजना को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के बारे में केन्द्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से चर्चा की।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की तथा राजस्थान में ऊर्जा और आवासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

जयपुर/नई दिल्ली, 20 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बिजली, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर भेंट की तथा राजस्थान में ऊर्जा और आवासन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

शर्मा ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा निकासी की योजना बनाई है, इस योजना में शामिल परियोजनाओं को ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर- थर्ड में शामिल कर केंद्र की तरफ से अधिकतम अनुदान शीघ्र स्वीकृत किया जाए।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान आग्रह किया कि जयपुर मेट्रो रेल फेज- 2 का संयुक्त उपक्रम (50:50) के तहत निर्माण की विस्तृत कार्य योजना को जल्द स्वीकृति प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण प्रस्तावित परियोजना के लिए केंद्रीय अंशदान की स्वीकृति से जयपुर वासियों के लिए एक सुदृढ़ , सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन की सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य को जल्द हासिल किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा एशियन डवलपमेंट बैंक एवं वल्ड बैंक के संयुक्त वित्त पोषण के माध्यम से संचालित आर. यू. आई. डी. पी. पांचवें चरण की परियोजना तैयार कर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिस पर केंद्रीय मंत्रालय का सकारात्मक सहयोग आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाएं मौजदू हैं जिनके सकारात्मक दोहन और प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए केंद्रीय सहयोग आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

प्र.मंत्री ने स्व. राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी

नयी दिल्ली, 20 अगस्त। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर बुधवार को यहां उनकी समाधि वीर भूमि पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की।

कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री की स्मृति में उनकी समाधि वीर भूमि में आज सुबह कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं तथा पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और भारत रत्न राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

■ प्रियंका गांधी व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वीर भूमि जाकर राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।

वाड्रा ने अपने पिता को याद करते हुए कहा "विरासत में आप से करुणा, प्रेम और देशभक्ति का धर्म मिला। हम दोनों राहुल और मैं, हमेशा यह धर्म निभायेंगे। न कोई तोड़ पाएगा, न कोई रोक पाएगा, न कभी हमारे कदम लड़खड़ायेंगे।" खरगे ने पूर्व प्रधानमंत्री के उल्लेखनीय कार्यों को याद किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, आज उनकी जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को मेरी श्रद्धांजलि।

जयपुर के दो प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी

पुलिस ने द पैलेस स्कूल व एसएमएस स्कूल का चप्पा-चप्पा छाना पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

■ द पैलेस स्कूल को जून व जुलाई में भी इसी तरह की धमकियाँ मिली थीं। पुलिस की सायबर टीम जांच कर रही है कि ई-मेल किस आईपी एड्रेस से लिखा गया था।

जयपुर, 20 अगस्त। राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित द पैलेस स्कूल और एसएमएस को बुधवार को फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है।

यह धमकी एक ईमेल के जरिए भेजी गई है, जिसने न सिर्फ स्कूल प्रशासन, बल्कि पूरे शहर के लोगों को दहशत में डाल दिया है। यह कोई पहला मौका नहीं है, जब इस स्कूल को निशाना बनाया गया है। इसी साल जून और जुलाई में भी इसी तरह की धमकियां आ चुकी हैं। हालांकि हर बार यह सिर्फ अफवाह साबित हुई है।

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर, करण शर्मा ने बताया कि द पैलेस स्कूल और एसएमएस को मंगलवार देर रात को मेल कर धमकी दी गई थी, स्कूल स्टाफ ने सुबह मेल देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। दोनों स्कूलों में बम निरोधक दस्ता, एटीएस और डॉग स्क्वॉड की टीम सर्च करने पहुंची। लेकिन कुछ नहीं मिला। बच्चों को वापस घर भेज दिया गया था। टीम ने स्कूलों के चप्पे-चप्पे पर छानबीन की।

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर ने बताया कि माणक चौक थाना इलाके में स्थित द पैलेस स्कूल को मेल किया गया था कि द पैलेस स्कूल के कक्षा 4-7 के क्लासरूम और टॉयलेट में 2 टीएनटी आईईडी विस्फोट होने वाला है। 1.45 बजे तक सभी बच्चों को बाहर निकाल लो। गौरतलब है कि द पैलेस स्कूल को तीन महीने में तीसरी बार धमकी मिली है।

वहीं एसएमएस स्कूल को भी मेल आया था, जिसका बुधवार सुबह पता चला। पता लगने पर स्कूल स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। बिना देर किए पूरे स्कूल को खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया।

स्कूल परिसर में बम निरोधक दस्ता, एटीएस और डॉग स्क्वॉड टीमों ने चप्पे-चप्पे की तलाशी ली, लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी कोई भी संदिग्ध वस्तु या बम नहीं मिला।

पुलिस उपायुक्त, जयपुर उत्तर करण शर्मा ने बताया कि सायबर टीम मेल के बारे में जानकारी जुटा रही है। मेल किस आईपी एड्रेस से लिखा गया है, इस पर काम किया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सायबर सेल की मदद से ईमेल भेजने वाले शख्स की तलाश कर रही है।

'नोबल शांति पुरस्कार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और अर्थव्यवस्था पर उनकी रेटिंग काफ़ी नकारात्मक हो गई है। आप्रवासन (इमिग्रेशन), जो उनके पुन: चुनाव अभियान का मुख्य मुद्दा था, पर भी असहमति बढ़ी है। यहाँ तक कि अपराध पर भी, जहाँ रिपब्लिकन आमतौर पर अधिक समर्थन पाते हैं, उनकी रेटिंग नीचे आई है।

राज्य स्तर पर ट्रंप की लोकप्रियता रिपब्लिकन गढ़ों में सबसे अधिक और डेमोक्रेटिक राज्यों में सबसे कम है। लेकिन "यू गव" के राज्यवार अनुमान दिखाते हैं कि 2024 में जो राज्य उन्होंने बाइडन से छीन लिए थे, वहाँ भी असंतोष गहरा है। प्रतिस्पर्धी मध्यावधि चुनावों का सामना कर रहे रिपब्लिकनों के लिए ये आँकड़े चिंताजनक हैं।

जनसांख्यिकी के हिसाब से अंतर साफ दिखता है। श्वेत और पुरुष मतदाता ट्रंप के सबसे बड़े समर्थक बने हुए हैं, जबकि महिलाएँ, युवा अमेरिकी और अल्पसंख्यक उनसे असहमति रखते हैं। कॉलेज स्नातक और स्नातकोत्तर राष्ट्रपति को सबसे कम समर्थन देते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि वृद्ध मतदाता, जो पिछले चुनावों में रिपब्लिकन का मज़बूत आधार रहे हैं, इस बार अपेक्षा से कम समर्थन दिखा रहे हैं।

जिन मुद्दों को अमेरिकी सबसे अहम मानते हैं, उन पर ट्रंप पिछड़ रहे हैं। महँगाई और कीमतें दोनों पार्टियों के मतदाताओं की सूची में सबसे ऊपर हैं, हालाँकि रिपब्लिकन (26 प्रतिशत) डेमोक्रेट्स (20 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा चिंतित हैं। नौकरियाँ और अर्थव्यवस्था दूसरे स्थान पर हैं, इसके बाद स्वास्थ्य सेवा आती है। डेमोक्रेट्स नागरिक अधिकारों, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता देते हैं, जबकि रिपब्लिकन का ध्यान आप्रवासन, राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी खर्च पर है। यह अंतर दिखाता है कि मतदाता राष्ट्रपति के कामकाज को "पार्टीगत नज़रिये" से आंकते हैं।

2017 से अब तक के साप्ताहिक सर्वेक्षणों पर नज़र डालें तो जनमत को प्रभावित करने वाले मुद्दे समय के साथ बदलते रहे हैं। ट्रंप के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएँ, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, सबसे बड़ा मुद्दा थीं। बाइडन के कार्यकाल में महँगाई और रूस के 2022 के यूक्रेन हमले का असर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा था। अब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में महँगाई, अर्थव्यवस्था और आप्रवासन उनकी राष्ट्रपति पद की सबसे कठिन कसौटियाँ बनी हुई हैं।

जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, आदमी अपना इतिहास बनाता है, लेकिन अपनी पसंद की परिस्थितियों में नहीं। डॉनल्ड ट्रंप के लिए, जनमत, जो आर्थिक तकलीफ़, वैश्विक संघर्षों और राजनीतिक ध्रुवीकरण से आकार लेता है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को सीमित करता जा रहा है, चाहे वे कितने भी वादे क्यों न करें।

दिल्ली के 50 स्कूलों को बम की धमकी

नई दिल्ली, 20 अगस्त। दिल्ली के करीब 50 स्कूलों को बुधवार सुबह ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। इनमें द्वारका के राहुल मॉडल स्कूल और मैक्सफोर्ट स्कूल, मालवीय नगर का एसकेवी और प्रसाद नगर का आंध्रा स्कूल शामिल हैं।

धमकी मिलने के तुरंत बाद ही दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई और पुलिस डॉग स्क्वायड की टीम, बम डिस्पोजल टीम और दमकल विभाग को लेकर अलग-अलग स्कूलों में पहुंच गई। अभी सभी स्कूलों की लिस्ट सामने नहीं आई है।

■ पुलिस ने सभी स्कूलों की गहन जांच की पर कुछ नहीं मिला।

स्कूलों को जैसे ही मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, पुलिस जांच में लग गई। खबर लिखे जाने तक पुलिस को किसी भी स्कूल में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है। ज्ञातव्य है कि दो दिन पहले यानी 18 अगस्त को भी द्वारका के डीपीएस सहित तीन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। वो धमकी भी मेल के जरिए की गई थी।आपको यह भी बता दें कि उससे पहले यानी 15 अगस्त को दिल्ली के द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल और दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन कॉलेज को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी।

'रुस पर दबाव डालने के लिए भारत पर टैरिफ लगाया है'

वाशिंगटन, 20 अगस्त। वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने रूस पर यूक्रेन युद्ध समाप्ति के लिये अतिरिक्त दबाव बनाने के लिये भारत पर "प्रतिबंधों" के रूप में आयात शुल्क लगाये हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर लगाये गये अमेरिकी प्रतिबंधों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ट्रम्प के साथ बैठक के लिये सहमत होने में भूमिका निभाई है। ट्रम्प ने पहले घोषित 25 प्रतिशत पर 25 प्रतिशत नया शुल्क जोड़कर भारत पर आयात शुल्क का बोझ दोगुना कर 50 प्रतिशत कर दिया।

लेविट ने संवाददाताओं को बताया कि, "यह कदम रूस पर" अतिरिक्त दबाव" डालने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा था। राष्ट्रपति ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ज़बरदस्त सार्वजनिक दबाव बनाया है। उन्होंने भारत पर प्रतिबंध और अन्य कदम उठाए हैं। उन्होंने खुद साफ़ कर दिया है कि वह इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय बैठक की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि रूस ने अब तक ठोस प्रतिबद्धताओं से परहेज किया है लेकिन उसने भविष्य में वार्ता की संभावना से इन्कार नहीं किया है।

नारकोटिक्स ब्यूरो ने इन्सपैक्टर और कांस्टेबल को बर्खास्त किया

■ चार व छह साल से नौकरी कर रहे इन दोनों की जगह किसी अन्य व्यक्ति ने परीक्षा दी थी।

■ नारकोटिक्स ब्यूरो को दोनों के खिलाफ शिकायतें मिली थीं, जब जांच करवाई गई तब इस फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ।

कोटा, 20 अगस्त (निसं)। प्रदेश में डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा देकर नौकरी पाने के कई मामले सामने आए हैं। रेलवे में भी हाल ही में इस तरह का मामला देखने को मिला था। अब ताजा मामला केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीएनबी) में सामने आया है जिसमें विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल को बर्खास्त कर दिया। ये दोनों क्रमश: 4 और 6 साल से नौकरी कर रहे थे। दोनों की नियुक्ति कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई थी लेकिन वास्तव में उनकी जगह किसी और व्यक्ति ने परीक्षा दी थी। इनके फोटो, हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहे थे। इसी पर विभाग को दोनों पर संदेह हुआ और उन्होंने जांच शुरू कर दी। जांच के बाद ही विभाग ने यह फैसला लिया।

केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के उपायुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि विभाग को दोनों के संबंध में शिकायत मिली थी जिसके बाद जांच कराई गई। यह पूरी जांच रिपोर्ट मुख्यालय भेज दी गई थी। इसके आधार पर दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार इंस्पेक्टर प्रदीप मूल रूप से हरियाणा निवासी हैं जिसने साल 2019 में फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त की थी।

वह वर्तमान में प्रतापगढ़ जिले में तैनात था, जबकि कांस्टेबल जाकिर हुसैन बिहार निवासी है। वह 2021 में नौकरी में आया था। उसके बाद कोटा में ही पदस्थ था। मामले में नारकोटिक्स ब्यूरो ने शिकायत के बाद दोनों आरोपियों के संबंधित दस्तावेज कर्मचारी चयन आयोग से मंगवाए थे। इन दस्तावेजों के आधार पर फोटो व फिंगर प्रिंट्स का मिलान कराया गया जिसके लिए नमूने भोपाल लैब में भेजे गए। इसमें प्रदीप के फोटो का मिलान हो गया लेकिन जाकिर हुसैन के फोटो का मिलान नहीं हुआ। इसके बाद प्रदीप के फिंगरप्रिंट की जांच जयपुर लैब में करवाई गई। जांच में पाया गया कि प्रदीप के नौकरी जॉइन करते समय लिए गए और परीक्षा के दौरान लिए गए फिंगरप्रिंट अलग-अलग थे। इसके अलावा दोनों के परीक्षा के दौरान दिए गए हस्ताक्षर और वर्तमान के हस्ताक्षर भी नहीं मिल रहे थे। इसके बाद सीधी कार्रवाई करते हुए दोनों को बर्खास्त कर दिया गया।

बर्खास्त इंस्पेक्टर प्रदीप और कांस्टेबल जाकिर हुसैन अब तक वेतन और भत्ते के रूप में लाखों रुपए प्राप्त कर चुके हैं।

ऐसे में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो दोनों आरोपियों से इस रकम की वसूली में जुटा हुआ है। दोनों आरोपियों को नोटिस देकर वेतन और भत्ते के रूप में लिए गए पैसे एक माह के भीतर वापस कराने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो पूरा मामला सीबीआई को भेजने की तैयारी में है।

अग्नि 5 ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसकी रेंज करीब 5000 किलोमीटर तक की है। अग्नि-5 की जद में पाकिस्तान-चीन समेत करीब आधी दुनिया का हिस्सा आता है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि अग्नि-5 मिसाइल मौजूदा परीक्षण में सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों पर खरी उतरी है।

'प्रेस रिलीज़ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कंपनियाँ (एन.पी.एल. और टी.एस.पी.एल.), जिन्हें पंजाब में थर्मल पावर प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए विशेष प्रयोजन इकाइयों के रूप में बनाया गया था, ने "टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली" के बाद पी.एस. पी.सी.एल. के साथ पावर परचेज़ एग्रीमेंट किया था। बाद में उन्होंने दावा किया कि सरकार के फ़ैसले और स्पष्टीकरण, जिनमें "मेगा पावर प्रोजेक्ट लाभ" पर प्रेस रिलीज़ और उसके बाद के डी.जी.एफ.टी. नोटिफिकेशन शामिल हैं, ने वित्तीय ढाँचे को बदल दिया और इस वजह से उन्हें कानून में बदलाव माना जाना चाहिए, जिससे उन्हें मुआवज़ा मिल सके।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जनसुनवाई के दौरान हमला हुआ

■ आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

नयी दिल्ली, 20 अगस्त। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान एक शख्स ने हमला कर दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के समय मुख्यमंत्री गुप्ता आम लोगों की शिकायतें सुन रहीं थीं। एक शख्स भी अपनी शिकायत लेकर वहां पहुंचा और उसने श्रीमती गुप्ता पर हमला कर दिया। उसके इस हमले की वजह का फिलहाल पता नहीं चला है।

पुलिस हमलावर शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुआ हमला बेहद निंदनीय है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध की जगह होती है, लेकिन हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।

उन्होंने कहा उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आशा है मुख्यमंत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं।

दिल्ली मुख्यमंत्री ने शाम करीब 6 बजे एक्स पर लिखा, जनसुनवाई के दौरान मेरे ऊपर हुआ हमला दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प पर कायराना प्रहार है। हमले के बाद सदमे में थी। अब बेहतर महसूस कर रही हूं।

सीएसडीएस के संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज

संजय कुमार पर महाराष्ट्र के लोकसभा व विधानसभा चुनावों में मतदाता सूची के भ्रामक आंकड़े देने का आरोप है

■ मामला दर्ज होने की जानकारी नासिक जिला चुनाव कार्यालय ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी।

नयी दिल्ली, 20 अगस्त। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की 2024 के चुनावों की मतदाता सूची के भ्रामक आंकड़े देने के मामले में सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के संजय कुमार पर नासिक में जिला चुनाव कार्यालय की तरफ से उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मतदाता सूची की भ्रामक जानकारी देने के मामले में एक दिन पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने संवाददाता सम्मेलन में सीएसडीएस के भ्रामक आंकड़ों को सार्वजनिक करने के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा था। यह मामला हालांकि सामने आने पर संजय कुमार ने एक्स पर एक पोस्ट में माफी मांगते हुए इस पोस्ट को पहले ही हटा लेने की बात कही थी।

संजय कुमार पर मामला दर्ज होने की जानकारी नासिक के जिला चुनाव कार्यालय द्वारा संचालित डीईओ नासिक पर एक एक्स पोस्ट के माध्यम से सामने आयी है। इस पोस्ट में लिखा गया है कि सीएसडीएस के संजय कुमार ने महाराष्ट्र लोकसभा 2024 और महाराष्ट्र विधान सभा 2024 के लिए 126-देवलाली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की भ्रामक जानकारी पोस्ट की है, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी केवल चुनाव आयोग की वेबसाइट से ही सत्यापित करें।

संजय कुमार ने 17 अगस्त को किये ट्वीट में बताया था कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वोटों की संख्या में काफी अंतर था। उन्होंने 100 विधानसभा सीटों का उदाहरण दिया था। अब उन्होंने इसे आंकड़ों का गलत विश्लेषण बताया है। संजय कुमार ने कहा कि उनकी टीम ने चुनाव आंकड़ों का गलत विश्लेषण किया था, इसके लिए उन्होंने माफी मांग ली थी।

राधाकृष्णन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के अलावा और भी कई केन्द्रीय मंत्री मौजूद थे। राधाकृष्णन का नामांकन चार सेटों में दाखिल हुआ है। जिनमें से प्रत्येक पर 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों के हस्ताक्षर हैं। पहले सेट में मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी के हस्ताक्षर हैं, जबकि बाकी सेटों में केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ राजग नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जो गठबंधन में व्यापक सहमति को दर्शाता है। उप राष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन के इस एतिहासिक मौके पर संसद भवन में नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान मंत्रियों और सांसदों सहित राजग के लगभग 160 सदस्य उपस्थित रहे। राधाकृष्णन को नामित करने का निर्णय केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी के आवास पर आयोजित राजग के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।

'बड़े बे आबरू ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

लौट गए ताकि अपना संघर्ष अगले दिन फिर जारी रख सकें।

वह व्यक्ति, जो कभी कांग्रेस पार्टी का किंग होता, क्योंकि सोनिया गांधी की पहली पसंद अध्यक्ष पद के लिए वही था, आज दरवाज़े-दरवाज़े काम माँग रहा है!!

इसे कहते हैं समय का फेर।

एलडीसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया कि शेष पदों को मंत्रालयिक पदों में शामिल कर बाद में भर्ती निकाल दी थी। ऐसे में भर्ती का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

'सिल्वर सॉइल इंडस्ट्रियल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आर सी ए अध्यक्ष सी पी जोशी के करीबी माने जाते थे। इस मामले में एन सी एल टी के समक्ष सुनवाई के दौरान अदालत ने हैरानी जताई कि 1 मार्च 2022 को आदेश दिए जाने के बाद भी उक्त प्रोजेक्ट की जमीन का बेचान कैसे किया जा रहा है जबकि बेचान पर रोक सम्बंधी आदेश 1 मार्च की शाम को ही एन सी एल टी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए थे। अदालत ने इस मामले में उन व्यक्तियों को भी पार्टी बनाया है, जिन्होंने 1 मार्च 2022 के बाद सिल्वर सॉइल प्रोजेक्ट की जमीन खरीदी जिनमें भवानी शंकर सामोता, उनकी पत्नी उर्मिला सामोता, उनकी कंपनी सामोता होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ राजेंद्र कुमार जैन, सीताराम यादव, सुनील अग्रवाल, रोहित कुमार अग्रवाल, बंशीधर यादव, अरुण कुमार अग्रवाल और मुकेश कुमार गुप्ता को भी पार्टी बनाया है और जवाब तलब किया है कि अदालत के आदेश के बावजूद उक्त प्रोजेक्ट की जमीन को कैसे बेचा गया और सेल डीड कैसे जारी करी गई। इस मामले में अदालत ने ग्राम चौमू तहसील गोविंदगढ़ के सब रजिस्ट्रार और स्टैम्प पेपर और रजिस्ट्रेशन जारी करने वाले इंस्पेक्टर जनरल को भी जवाब तलब किया है कि कैसे उन्होंने उक्त मामले में सिल्वर सॉइल प्रोजेक्ट की जमीन के बेचान की सेल डीड जारी की जबकि अदालत ने इसकी रोक पर स्पष्ट आदेश दिए थे और याचिकाकर्ता सत्यनारायण गुप्ता ने भी दोनों अधिकारियों को अदालती आदेश के संबंध में जानकारी दी थी। अदालत ने पुन: आदेश में कहा कि इस मामले में आगे भी बेचान किया गया और सेल डीड जारी की गई तो अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले की अगली तारीख 4 सितंबर तय करी गई है।

भर्ती परीक्षाओं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसी तरह पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में मूल अभ्यर्थी सागर मीणा को गिरफ्तार किया गया है।

सागर नांगल बरसी सदर दौसा का रहने वाला है और वर्तमान में देवला की डांग नसीराबाद अजमेर में पटवारी है। पूर्व में इसकी जगह डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा देने वाले रोशन लाल मीणा को एस.ओ.जी. गिरफ्तार कर चुकी है। इसके अलावा एसओजी ने पीटीआई भर्ती परीक्षा 2022 में मुल्जिम सौरव कलाल, निवासी कलालवाड़ा भुगडा बांसवाड़ा, को गिरफ्तार किया है।

वर्तमान में यह राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बांसवाड़ा में पीटीआई है। इस संबंध में एसओजी पूर्व में प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रदीप के मार्फत जेएस यूनिवर्सिटी से बैक डेट में बीपीएड की फर्जी डिग्री प्राप्त की थी।

"इंटिग्रिटी बिल" के मार्फत बहुत "ऊंचा"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

धारणा" के सिद्धांत को उलट देता है और जांच एजेंसियों को निर्वाचित नेताओं-यहाँ तक कि प्रधानमंत्री- से ही ऊपर रख देता है। उन्होंने कहा, "यह देश के सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख को एक जांच अधिकारी के अधीन बना देता है, जो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।"

एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे "गेस्टापो-शैली की पुलिसिंग" करार दिया और चेतावनी दी कि इससे जांच एजेंसियों को सरकार गिराने की अभूतपूर्व ताकत मिल जाएगी।

प्रियंका गांधी ने इस कदम को "क्रूर" बताया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को उदाहरण के रूप में पेश किया कि कैसे कमजोर आरोपों का राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग हो सकता है। वामपंथी दलों ने इसे "लोकतंत्र और संघीय ढांचे पर सीधा हमला" कहा।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कदम का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इसका विषयवस्तु। संसद सत्र समाप्त होने के कगार पर है और देश आर्थिक तनाव, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रहा है-ऐसे समय में इस विधेयकों को अचानक लाना केवल शासन-सुधार नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है।

राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि इसका छिपा हुआ उद्देश्य भाजपा का अपने सहयोगियों-खासतौर पर एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों-पर दबाव बनाना हो सकता है, जो अब खुद को केंद्रीय एजेंसियों की जांच की चपेट में पा सकते हैं। उन्होंने कहा, "यह केवल विपक्ष की बात नहीं है; सहयोगियों को भी उतनी ही चिंता होनी चाहिए।"

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने इसका समर्थन किया तथा कहा, "यह विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि जब संविधान बना था, तब शायद हमारे संस्थापक यह कल्पना नहीं कर पाए थे कि सत्ता में बैठे लोग इतने भ्रष्ट और आपराधिक हो जाएंगे कि जेल जाने की नौबत आ जाएगी और वे जेल में रहते हुए भी पद नहीं छोड़ेंगे। मेरा मानना है कि यह एक अच्छा विधेयक है-अगर कोई नेता आरोपी है और जेल में है, तो वह सरकार नहीं चला सकता।"

विश्लेषक इस पर बँटे हुए हैं। एक ओर, इसे राजनीतिक जीवन में नैतिकता और जवाबदेही के उच्च मानकों की दिशा में साहसिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, इसे एक खतरनाक राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जा रहा है जो संवैधानिक सुरक्षा-प्रणाली को कमज़ोर करता है और सत्ता को केंद्र में केंद्रीकृत करता है।

ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सिर्फ कोई ध्यान भटकाने वाला प्रयास नहीं, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक जुआ है जिसमें भारी दांव लगा है। इन विधेयकों का भविष्य अब संभवत: संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास जाएगा और यदि पारित हो जाते हैं तो न्यायिक समीक्षा का सामना करेंगे।

फिलहाल, एक बात स्पष्ट है: मोदी सरकार ने संसद सत्र को सहमति की भावना के साथ समाप्त करने के बजाय टकराव की स्थिति में ला खड़ा किया है-और राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान हटाकर भारतीय लोकतंत्र के भविष्य पर बहस को केंद्र में ला दिया है।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय:-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908